संपादकीय

राजस्थान की नई पाठ्यपुस्तकें
नौ दिन चले अढ़ाई कोस

राजस्थान में आरंभिक स्तर के लिए कुछ कक्षाओं की नई पाठ्यपुस्तकें इस सत्र से स्कूलों में लागू हुई हैं। अभी तक हिन्दी की कक्षा 1, 3, 5; पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3, 5; गणित की कक्षा 1, 3, 5; सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6, 7 तथा अंग्रेजी की कक्षा 1, 3, 5, 6, 7 एवं 8 की पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। शिक्षा विमर्श का यह अंक मुख्यतः इन पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा पर केन्द्रित है। पहली नजर में यह पाठ्यपुस्तकें पुरानी की बनिस्बत बेहतर दिखाई देती हैं। पाठ्यपुस्तक निर्माताओं ने इन्हें छपाई एवं साज-सज्जा में पहले से अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की है।

पुरानी पाठ्यपुस्तकों में तमाम विचारधारात्मक एवं शिक्षाशास्त्रीय खामियों के चलते नई पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें बनाने की मांग राजस्थान के विभिन्न शैक्षिक एवं नागरिक संगठनों ने वर्ष 2006 से शुरू की थी (तत्कालीन पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा पर शिक्षा विमर्श का एक अंक जनवरी-फरवरी, 2007 में प्रकाशित हुआ है)। दरअसल, तब तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (एनसीएफ 2005) आ चुकी थी और इसके अनुरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित कुछ कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें भी सामने आ चुकी थीं। शैक्षिक एवं नागरिक संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नई पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकें बनने तक स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें पढ़ाने का निर्णय लिया।

इस परिदृश्य में उम्मीद की जा रही थी कि एनसीएफ 2005 और एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों से प्रेरणा लेते हुए नई पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें राजस्थान के बच्चों के लिए बेहतर संदर्भ उपलब्ध कराएंगी। एनसीएफ 2005 के सिद्धान्तों का मंत्र जाप करने के बावजूद पहले चरण में आई पाठ्यपुस्तकों को (अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों के बारे में समीक्षक की राय है कि यह एनसीएफ 2005 के सिद्धान्तों के अनुरूप और रोचक हैं) देखकर नहीं लगता कि पाठ्यपुस्तक निर्माताओं ने एनसीएफ 2005 एवं एनसीईआरटी की नई पाठ्यपुस्तकों से कुछ खास सीखा है। सवाल यह है कि हमारे सामने एनसीईआरटी की मौजूद एक मिसाल के बावजूद राजस्थान की यह पाठ्यपुस्तकें क्यों अपेक्षित मानकों के नजदीक तक नहीं पहुंच पाई हैं?

प्रक्रियात्मक गड़बड़ी

एनसीईआरटी ने पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण की क्रमिक प्रक्रिया, बौद्धिक और अकादमिक विचार विमर्श और व्यापक बहस-मुबाहिसे की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जरूरत को भी रेखांकित किया है। पाठ्यपुस्तक निर्माण की अनिवार्य पूर्वशर्त पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम हैं। लेकिन राजस्थान में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें बनाने की प्रक्रियाएं एक-दूसरे से अलग-थलग चलती रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों के विकास से पूर्व पाठ्यचर्या जैसे दस्तावेज के निर्माण की आवश्यकता नहीं महसूस की गई। राजस्थान के शैक्षिक एवं नागरिक संगठनों ने मांग की थी कि इस प्रक्रिया को विधिवत पूरा किया जाए। अर्थात् पहले पाठ्यचर्या निर्मित की जाए, उसके बाद पाठ्यक्रम और अन्त में पाठ्यपुस्तकें।

इस मांग के परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार ने पाठ्यचर्या निर्माण के लिए प्रो. पी. सी. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था (यह समिति अपने कार्य के प्रति कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया और उससे उत्पन्न दस्तावेज को देखकर लगाया जा सकता है)। लेकिन इस समिति के द्वारा पाठ्यचर्या दस्तावेज निर्मित किए जाने से पहले ही राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईआरटी) ने आईसीआईसीआई फाउण्डेशन के साथ मिलकर पाठ्यपुस्तक निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। इस दरम्यान एसआईईआरटी और पाठ्यचर्या के लिए गठित समिति के बीच किसी तरह की अन्तःक्रिया भी नहीं हुई। इसके समानान्तर एसआईईआरटी और फाउण्डेशन ने पाठ्यक्रम के नाम पर पांच अलग-अलग दस्तावेज निर्मित किए हैं। इन दस्तावेजों के प्रति दोनों संस्थानों की गंभीरता का पता इसी बात से चलता है कि यह दस्तावेज अभी भी ड्राफ्ट के रूप में ही मौजूद हैं और इनमें से तीन हिन्दी में तैयार किए गए हैं और दो अंग्रेजी में। हिन्दी के दस्तावेजों का यथोचित संपादन भी नहीं किया गया है। इन दस्तावेजों को पाठ्यक्रम के तौर पर एक कवर में व्यवस्थित न करना और हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में बने रहने देना संभवतः प्रक्रियात्मक खानापूर्ति को ही दर्शाता है। ऐसा भी लगता है कि पाठ्यक्रम निर्माताओं की नजर में यह दस्तावेज शिक्षकों के लिए उपयोगी नहीं हैं।

हालांकि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के सदस्यों को देखकर लगता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को वैधानिकता प्रदान करने के लिए देशभर के विभिन्न प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के सदस्यों को शामिल किया गया है लेकिन पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता इसके कागजी होने को ही साबित करती है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस राज्य स्तरीय उपक्रम में बिना व्यापक भागीदारी और बहस-मुबाहिसे को सुनिश्चित किए एसआईईआरटी ने अपनी स्वायत्ता को फाउण्डेशन के नियंत्रण के लिए खुला छोड़ दिया। पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया में इस गड़बड़ी का असर स्पष्ट रूप से पाठ्यपुस्तकों में देखा जा सकता है।

कोरे दावे

राजस्थान में नव-निर्मित पाठ्यपुस्तकें एनसीएफ के सिद्धान्तों के अनुरूप होने का दावा करती हैं। पाठ्यपुस्तकों पर चर्चा करने से पहले पाठ्यपुस्तक के आमुख में किए गए दावों पर दृष्टि डालना उपयुक्त होगा, ''पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण के दौरान हमने यह विशेष ध्यान रखा है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। उन्हें करके देखने, समझ बनाने, गलती करने तथा अपनी गलतियों को स्वयं ठीक करने के समुचित अवसर मिलने चाहिए। इस तरह वे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं।...अतः बच्चों के स्वभाव, उनकी रुचियों और आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए विषय सामग्री और गतिविधियां तैयार की गईं।... भारत की विविधता भरी संस्कृति, हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ ही जेण्डर, धर्म, जाति, भाषायी विविधता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए समावेशी शिक्षा के विचार को समाहित करने का प्रयास किया गया।''

उपरोक्त अंश में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पाठ्यपुस्तक के आमुख में लगभग वे सभी दावे किए गए हैं जिन्हें वर्तमान शैक्षिक विमर्श में प्रगतिशील माना जाता है। हालांकि किए गए दावों पर यह किताबें कितना खरी उतरती

हैं, इसका जायजा पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण से चलता है। दिलचस्प बात यह है कि पाठ्यपुस्तक के आमुख में किए गए एनसीएफ 2005 के तमाम दावों में स्थानीय ज्ञान को कक्षा-कक्ष में लाने और विवेचनात्मक चिन्तन के विचार का जिक्र तक नहीं किया गया है। शायद यही वजह है कि यह पाठ्यपुस्तकें बच्चे के परिवेश, खासकर सामाजिक परिवेश, से ऐसे किन्हीं मुद्दों को कक्षा में विचार विमर्श का विषय नहीं बनातीं जो विवादित हैं। जाति, जेण्डर एवं धार्मिक समता के विचार को अन-आलोचनात्मक रूप से सिर्फ व्याख्यान की शैली में परोस दिया गया है। कहीं से भी यह पाठ्यपुस्तकें बच्चों के आलोचनात्मक चिन्तन को नहीं उकसाती हैं। अवधारणाओं के बोझ को भी बच्चों पर भरपूर लादा गया है। उदाहरण के लिए, कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की किताब में 'जेण्डर भेदभाव की समझ' नामक अध्याय में जेण्डर भेदभाव के सामाजिक आयाम, महिला आन्दोलन, महिला राजनीतिक नेतृत्व, महिला संरक्षण के कानून, महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानून आदि को मात्र सात पृष्ठों में समेट दिया गया है। साथ ही भारी-भरकम ज्ञान को देने से परहेज नहीं किया है, सीमोन द बोउवार के कथन को बस उद्धृत भर कर दिया है, ''स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है।'' बच्चों के करके देखने के लिए आकर्षक शीर्षक ''आओ करके देखें'' में ''बताओ कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हैं?'' सूचना और करके देखने के फर्क को भी मिटा दिया है।

हिन्दी और अन्य पाठ्यपुस्तकों के आमुख में जोर-शोर से 'भाषायी विविधता (बहुभाषिकता) को उनके (बच्चों के) सीखने का मजबूत आधार माना गया'' है। भाषायी विविधता को शिक्षा प्रक्रियाओं में स्थान देना निश्चित ही बच्चों के सीखने में एक महत्त्वपूर्ण आयाम होता है। हालांकि पाठ्यपुस्तकों में बहुभाषिकता के सिद्धान्त के इस्तेमाल पर पाठ्यपुस्तक निर्माता समूह की स्पष्टता नजर नहीं आती। सही मायने में पाठ्यपुस्तकों में इस सिद्धान्त के क्या निहितार्थ हैं, इसे तलाशा नहीं गया है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों की भाषाओं की चन्द रचनाओं को शामिल करके या एकत्रित करने के कुछ निर्देश से ही बहुभाषिकता के सिद्धान्त की इतिश्री मान लिया गया है। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में रचनाओं के चयन में अनेक समस्याएं हैं। यह रचनाएं भाषा के कृत्रिम और नीरस प्रयोग के चलते बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं करेंगी।

छपाई एवं साज-सज्जा

निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि राजस्थान की नई पाठ्यपुस्तकों को छपाई और साज-सज्जा के लिहाज से पुरानी की बनिस्बत बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। ले-आउट और डिजाइन में चार रंगों का इस्तेमाल है लेकिन पेपर की गुणवत्ता ने इसके साथ समुचित न्याय नहीं होने दिया है। इसी वजह से सभी पाठ्यपुस्तकों में रंग बिखर गए हैं। अनेक स्थलों पर इसकी वजह से कुछ अच्छे प्रयोग भी बलि चढ़ गए हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 में असमानता पर बात करते हुए अखबार के 'वैवाहिकी' विज्ञापन का उपयोग किया गया है। छपाई की गुणवत्ता के चलते इसे पढ़ पाना असंभव है। संभवतः पाठ्यपुस्तकों की लागत को कम करने के लिए जिल्द पर ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ ही दिनों में पाठ्यपुस्तक का कवर और शेष पुस्तक बच्चों के हाथ में अलग-अलग होंगी।

अन्त में

एनसीएफ 2005 के बाद जो उम्मीद की जा रही थी कि राजस्थान की नई पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकें न सिर्फ पहले से बेहतर होंगी बल्कि हमारे बीच एनसीईआरटी द्वारा स्थापित मानकों के करीब पहुंचने में मदद करेंगी। लेकिन राजस्थान के बच्चों के लिए एनसीएफ 2005 के बाद अच्छी किताबें मिल पाने की संभावना को फिर से पता नहीं कितने सालों के लिए पीछे धकेल दिया है। एनसीएफ 2005 के आठ साल बाद यह किताबें संभव हुई हैं। अब पता नहीं कब जाकर इनमें सुधार की गुंजाइश बनेगी। राजस्थान की पाठ्यपुस्तकों को देखकर नौ दिन चले अढ़ाई कोस की कहावत ही चरितार्थ होती प्रतीत होती है। ◆